Subject: **विषय :- टैरिफ 2017 के लागू होने के पश्चात से केबल आपरेटरों को हो रहे भारी नुकसान ओर टैरिफ 2017 मे संशोधन के संदर्भ में।**

Date: 09/09/19 01:33 PM

From: Subhkant Kamat <kamatcable1@gmail.com>

To: cp@trai.gov.in, arvind@gov.in, secretary@trai.gov.in, section officer <sectionofficerdas@gmail.com>, secy.inb@nic.in, vk.agarwal@trai.gov.in

सेवा मे,
श्रीमान राम सेवक शर्मा जी
माननीय चेयरमैन साहब टी.आर.ए.आई ।

विषय :- टैरिफ 2017 के लागू होने के पश्चात से केबल आपरेटरों को हो रहे भारी नुकसान ओर टैरिफ 2017 मे संशोधन के संदर्भ में।

मान्यवर,
सादर नमस्कार शुभ कांत कामत केबल ऑपरेटर हूँ। कामत केबल टीवी नेटवर्क दिल्ली
महोदय मै आपका ध्यान ईस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्रयोग टैरिफ 2017 के रूप मे किया है।
ये कितना सफल/असफल हुआ आप के पास आंकड़े आ ही रहे होंगे।
मगर ईसमे केबल ऑपरेटरों के साथ क्या हुआ है ये जानना भी आवश्यक है।
महोदय ये केबल व्यवसाय हम केबल ऑपरेटरों ने अनेक वर्षों से अपने खून पसीने से सींचकर कई हजार करोड़ का ऐसे ही नहीं बनाया बल्कि जनता/ उपभोक्ताओं के साथ हमारे व्यवहार ओर आपसी तालमेल का भी नतीजा है। हमने भाभी जी, बहनजी, माताजी बोलकर व्यवहार बनाया है ओर आज आपके टैरिफ रुपी प्रयोग से हमारे ईस व्यापार पर व्यवहार पर ओर आपसी तालमेल पर ग्रहण लग गया है।
महोदय ईस टैरिफ 2017 के लागू होने के पश्चात से जितना नुकसान केबल ऑपरेटरों का हुआ है ओर किसी का नही हुआ।
महोदय मेरे खुद के नेटवर्क के हालात इतने खराब हुए हैं कि हमारे लगभग 60% उपभोक्ताओं ने केबल देखना बंद कर दिया है क्योंकि उपभोक्ताओं का मासिक बिल डेड-दोगुना अधिक हो गया जिससे कि उपयोक्ताओं ने जिनके घरों मे 2-3 टी.वी चलते थे वो अब सिर्फ एक टी.वी तक सीमित रह गए हैं। जिससे हम लोगो का वितिय संतुलन ईतना गड़बड़ा गया कि हम लोग अपने 20-20 वर्ष पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर मजबूर हो गए ओर ईसके चलते उपभोक्ताओं को पूर्ण रुप से सेवा देने मे भी नाकाम होने लगे।
ओर ये सब आपके टैरिफ 2017 की मारक क्षमता का असर है जिसका प्रयोग सीधे-सीधे केबल ऑपरेटरों को लक्ष्य बना रहा है।
महोदय आपने बहुत बड़ा शुभचिंतक बनकर अपने राहू (टैरिफ2017) को हमारा (केबल ऑपरेटरों का) ग्रास बनाने का आदेश दे दिया है जिसका वो राहू (टैरिफ) पालन भी कर रहा है ओर हम लोगों को तिल तिल ग्रास बना रहा है।

महोदय मै आपका ध्यान ईसलिए भंग करना चाह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान मे आया है कि आप एक ओर नया प्रयोग करने जा रहे हैं मतलब अपने पुराने प्रयोग मे संशोधन करने जा रहे हैं।
क्योंकि मोजूदा प्रयोग के पश्चात जो नतीजे निकलकर आए ईससे
आपको उपभोक्ताओं के मनोरंजन) मासिक शुल्क की चिंता तो सता रही है मगर केबल ऑपरेटरों की नहीं।
आपकी ईस चिंता ने हम लोगों की चिंता ओर बढा दी है कहीं आपकी ये चिंता केबल ऑपरेटरों की चिता न बन जाए जैसा कि अनेक मामलों मे हो भी चुका है।
महोदय ये हम भी मानते हैं कि समस्या विकट हो चुकी है ओर आपने उसपर सुझाव भी मांगे हैं।

तो महोदय ईसपर मेरा सुझाव ईस प्रकार है कि :-
(1) ईस व्यवसाय पर से GST जो 18% है उसको कम करके 5% किया जाना चाहिए क्योंकि यदि उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क 350 रु.बनता है तो उस पर 18% GST
मिलाकर 411 रुपये हो जाता है।
जो कि उपभोक्ताओं की पहुंच से पार हो जाता है।
(ईस संदर्भ मे मैने GST Council ओर pmo को भी निवेदन किया है कृपया trai भी प्रयास करे तो अमल मे लाया जा सकता है)
(2) 15% कैपिंग जिसको आधार बनाकर ये टैरिफ 2017 लाया गया आप ईस संदर्भ मे बेहतर जानते हैं कि ईसके लागू होने पर किस प्रकार व्यवसाय जगत को कितना फायदा हो सकता है। यदि trai 15% कैपिंग नही ला पाई तो ईस टैरिफ का औचित्य स्वत: खत्म हो जाता है।
(3) चैनलो का मूलय निर्धारण सरकार द्वारा किया जाए ओर अधिकतम 19 रुपये से हटाकर 5 रुपये होना चाहिए।
ये 19 रुपये का निर्धारण ही ईस व्यवसाय की कमर तोड़ रहा है।
जिसके चलते उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क उनकी पहुँच से बाहर हो जाता है। ओर वो 2-3 टीवी से 1 पर आ गए हैं।
(4) ईस टैरिफ 2017 में केबल ऑपरेटर्स जो ईस व्यवसाय का सबसे अहम सतंभ हैं ईसपर पूरा ध्यान नही दिया गया हालांकि दूसरे-तीसरे ncf मे थोड़ी राहत मिलती है मगर ये भी पूरा ncf केबल ऑपरेटर्स का होना चाहिए था जब केबल ऑपरेटरों को कुछ बचेगा ही नहीं तो उपभोक्ताओं को सेवाऐं कैसे दे पाएंगे।
(5) यदि आप पुराने ढर्रे पर वापिस जाना चाहते हैं तो लौट सकते हैं।
(6) एमएसओ की मनमानी पर रोक लगे जो बिना वजह अपने तरीके से पैकेज बना रही है और जबरदस्ती ग्राहकों को थोप रही है फिर उस पैकेज के अंदर उन्हीं चैनलों को डाला जाता है जिनके पैसे एमएसओ को मिलते हैं और यह दोनों ब्रॉडकास्टर और एमएसओ की मिलीभगत से हो रहा है इस पर लगाम लगनी चाहिए
(7) यदि ब्रॉडकास्टर और एमएसओ की मनमानी को रोक देते हैं तो कई चैनल सस्ते हो जाएंगे और इस प्रकार ग्राहकों का पैसा भी कम हो जाएगा
(8)जब ब्रॉडकास्टर ने अपने पैकेज बना रखे हैं तो एमएसओ क्यों जबरदस्ती पैकेज बनाकर ग्राउंड पर डाल रहा है और केबल ऑपरेटर की सूचना के बगैर किसी भी चैनल को हटा देता है या लगा देता है इस तरह की मनमानी वह क्यों कर रहा है अति शीघ्र पर रोक लगे
(9) ब्रॉडकास्टर का जो 80 परसेंट दिया जा रहा है उसे मात्र 30 परसेंट दिया जाए बाकी 60% परसेंट केबल ऑपरेटर और एमएसओ में बांटा जाए जिसमें केबल ऑपरेटर को 40% और एमएसओ को 20% क्योंकि ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा कमाता है एमएसओ कैरिज लेता है और लोकल चैनल पर ऐड भी चलाकर कमाता है जबकि केबल ऑपरेटर के पास कोई और कमाई का जरिया नहीं है
(10) सभी एमएसओ को बोला जाए कि केबल ऑपरेटर के पोर्टल में सभी एफ टी ए चैनल डाले जाएं और सभी पे चैनल डाले जाएं ऑपरेटर ग्राहकों के द्वारा चुने हुए चैनल को दे सके और उनकी अधिकार का ध्यान रख सके ताकि जो ग्राहक चैनल मांगेगा वह उसको प्राप्त हो सके
(11) हमारे टेरिफ ऑर्डर में कानून का प्रावधान नहीं दिया गया है ऐसा प्रतीत होता है यदि कोई भी एमएसओ ब्रॉडकास्टर या एल सी ओ कानून का उल्लंघन करता है तो सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और वह किस किस धारा में कार्रवाई होगी उसकी सूचना लोकल पुलिस थाने के एसएचओ को या एसडीएम को दी जाए ताकि उन पर उचित कार्रवाई हो सके

(12) टीडी सेट के अंदर जो चार्ज लगता है ₹5000 का वह कम किया जाए ताकि केबल ऑपरेटर आसानी से इंसाफ पाने के लिए कोर्ट जा सकें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इतना चार्ज नहीं लगता जितना टीडी सेट में चार्ज लगता है
(13) टीडी सेट में कुछ सुझाव ऐसे दिया जाए ताकि यदि कोई एमएसओ किसी केबल ऑपरेटर की लाइन बंद कर देता है बिना सूचना के तो जो नुकसान केबल ऑपरेटर होता है उसकी भरपाई एमएस शो द्वारा किया जाए
(14) कानूनी प्रावधान इतने मजबूत हो कि एमएसओ और ब्रॉडकास्टर और केबल ऑपरेटर उस कानून को मानने के लिए मजबूर हो वरना भारी जुर्माना देने के लिए तैयार रहें वह जेल जाने तक का प्रावधान हो इस तरह का प्रावधान होगा तो कोई भी ब्रॉडकास्टर एमएसओएल एलसीओ कानून तोड़ने का सोच भी नहीं सकें
(15) एमएसओ लाइसेंस और आईएसपी लाइसेंस के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए ताकि लोकल केबल ऑपरेटर भी आसानी से उन लाइसेंसों को प्राप्त कर सके और अपने काम को कानूनी तौर पर सही तरीके से स्वयं कर सकें
(16) एमसीडी पीडब्ल्यूडी एनडीएमसी वह देश के जो भी महानगर है उनके ऐसे अधिकारी उनको आदेश दिया जाए कि भारत सरकार ने जो स्वच्छता अभियान चालू किया हुआ है उसके अंतर्गत ओवरहेड वायर ले जाने के लिए भी आने वाले समय में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उसके लिए सभी डिपार्टमेंट बहुत ही लोअर कॉस्ट पर उनको अंडर ग्राउंड परमिशन दें अति शीघ्र दें ताकि काम को और अच्छाई के रास्ते से करते हुए अच्छा डिजिटल नेटवर्क को ग्राहक तक पहुंचाया जा सके इसका भी प्रावधान इसमें होना चाहिए जो मात्र ₹10 हो पर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि हम तो यह कहेंगे कि सरकार ही इस कार्य को करके दे इतना कम पैसा इसलिए क्योंकि केबल ऑपरेटरों की तादाद बहुत ज्यादा है जो बहुत ही कम पैसों में अपना कार्य कर रहे हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है जो लाखों रुपए अंडरग्राउंड पर खर्च कर सकें

महोदय आप चाहे तो पुराने कानून पर भी जा सकते हैं जहाँ आपरेटरों का शोषण तो हो रहा था मगर धक्का स्टार्ट वाहन की तरह ही सही कुछ तो व्यवसाय चल रहा था।
उपभोक्ताओं को सस्ता मनोरंजन भी मिल ही रहा था।
मगर अब तो हमारे उपरोक्त व्यवसाय मे ब्रेक लग चुकी है ।
महोदय आपने जो ये ईतना भयंकर प्रयोग ईस केबल व्यवसाय जगत के साथ किया है। उसका सबसे अधिक असर केबल आपरेटरों को पर पड़ा है।

संज्ञान रहे ये किसी प्रकार की मंदी का असर नही बल्कि आपके उस टैरिफ रुपी प्रयोग का असर है।
जिस कारण हम आपरेटरों को अपने आफिस बंद करने पड़ रहे हैं।
बिजली का बिल नही भर पा रहे कर्मचारियों को काम से निकालना पड़ रहा है जिसका सीधा असर हम लोगों के घरों के चूल्हे पर तो पड़ ही रहा है। साथ ही हम लोग कर्मचारियों की कमी के रहते उपभोक्ताओं को सेवाएं देने मे असमर्थ हो रहे हैं।
महोदय जो ये हालात मै आपसे साझा कर रहा हूँ यही हालात देशभर के सभी आपरेटरों के हैं।

क्यूँ दी जाती है हर बार हमे,अन्जानी सी सजा।
पूछ सकते हैं साहब, आखिर हमारा कुसूर क्या है।

महोदय आपसे नम्र निवेदन है कृपया उपरोक्त बातों को ध्यान मे रखकर ही कोई संशोधन करें।

अन्यथा उन बातों को बल मिलेगा जो कि जो कि एक रसूखदार को फायदा पहुंचाने के लिए 60 हजार केबल आपरेटरों ओर लगभग 2.50 लाख कर्मचारियों ओर हम सबके परिवारों को आग मे झोंक दिया गया।
धन्यवाद महोदय
शुभ कांत कामत
सेवा प्रदाता /केबल आपरेटर (Den digital siti cable)
वरिष्ठ सदस्य (COWF INDIA)
साझीदार (independent mso ADPL)
सम्पर्क सूत्र 9717197641
ई मेल :-kamatcable1@gmail.com